Absence of SCs in Arunachal Pradesh

1370. SHRI NYODEK YONGGAM: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that as per the letter written to his Ministry by Government of Arunachal Pradesh in 1989, there is no schedule caste in the State of Arunachal-Pradesh; and

(b) if so, what is the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESARI): (a) Yes Sir,

(b) The details cannot be disclosed in the Pubblic interest.

राजभर/भर जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाना

1871. **श्री राम नरेश यादव** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजभर/भर जाति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 342(2) के अनुसार अनुसुचित जनजाति की सूची में सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिए जाने की सम्भावना है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भर/राजभर विमुक्ति जाति को अनुसूचित जातियों, अनुसुचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने के संबंध में सरकार को भारतीय राजभर महासभा से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) से (घ) सरकार को भारतीय राजभर महासभा से उन्हें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सुची में शामिल करने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और अधिक ब्यौरे लोकहित में प्रकट नहीं किए जा सकते।

डा० गोपालसिंह समिति की सिफारिशों को लागू किया जाना

1872. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए नियुक्त की गई डा० गोपाल सिंह समिति की सिफारिशों के संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ख) इस समिति ने क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) और (ख) अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों के अन्य कमजोर वर्गों से संबंधित उच्च अधिकार प्राप्त पेनल की रिपोर्ट 24 अगस्त, 1990 को राज्य सभा पटल पर रख दी गई थी। अल्पसंख्यकों से संबंधित सिफारिशों पर सरकार का दृष्टिकोण रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत विवरण में दे दिया गया था।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित रिपोर्ट विचाराधीन हैं।

15-Point Programme for Minorities

1873. DR. ABRAR AHMED: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the 15-Point programme announced by the then Prime Minister Shrimati Indira Gandhi for the minorities has been withdrawn;